बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 42 ● नई दिल्ली ● शुक्रवार 21 नवम्बर 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

16 साल के छात्र ने मेट्रो के आगे लगाई छलांग, सुसाइड नोट में हुआ बड़ा खुलासा

नई दिल्ली। दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले 16 साल के छात्र ने राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। घटना मंगलवार सुबह हुई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस के अनुसार, छात्र के स्कूल बैग से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने साफ लिखा है कि स्कूल के कुछ शिक्षक उसे मानसिक रूप से परेशान करते थे, जिसकी वजह से उसने यह कदम उठाया। नोट में उसने परिवार से माफी मांगते हुए अपने अंग दान करने की इच्छा भी व्यक्त की। उसने यह भी लिखा कि उसकी मौत का जिम्मेदार सिर्फ स्कूल का स्टाफ है और आगे किसी बच्चे के साथ ऐसा न हो। परिवार का कहना है कि लड़का कई बार घर आकर बताता था कि कुछ शिक्षक उसे छोटी-छोटी बातों पर डांटते हैं, क्लास में बेइज्जत करते हैं.

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: अदालत बिल मंजूरी की टाइमलाइन तय नहीं कर सकती; राष्ट्रपति संदर्भ केस में सीजेआई की पीठ

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को राष्ट्रपति के उस संदर्भ पर अपना फैसला सुनाया है, जिसमें पूछा गया था कि क्या कोई सांविधानिक अदालत, राज्य विधानसभाओं से पारित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समय-सीमा तय कर सकती है। इस मामले में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदुरकर की संविधान पीठ ने 10 दिनों तक दलीलें सुनीं और 11 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को राय विधानसभा से पारित विधेयकों पर अनुमोदन देने के लिए न्यायपालिका कोई समयसीमा तय नहीं कर सकती। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने राष्ट्रपति की तरफ से अनुच्छेद 143 के तहत भेजे गए 14 संवैधानिक प्रश्नों पर अपनी राय देते हुए कहा कि यह विषय संवैधानिक पदाधिकारियों के विवेक और संघीय ढांचे की मर्यादा से जुड़ा है। अदालत ने माना कि विधायी प्रक्रिया में राष्ट्रपति और राज्यपाल की भूमिका संवैधानिक कर्तव्य है, पर न्यायिक हस्तक्षेप के जरिए इसकी समय सीमा तय नहीं की जा सकती। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि अत्यधिक देरी लोकतांत्रिक शासन की आत्मा को क्षति पहुंचाती है, इसलिए इन पदों से अपेक्षा है कि वे उचित समय के भीतर निर्णय लें।

संविधानिक प्रावधान और राष्ट्रपति का कदम

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मई में संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी थी। उन्होंने पूछा था कि क्या न्यायालय यह तय कर सकता है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल को बिलों पर कब तक निर्णय लेना चाहिए। राष्ट्रपति ने अपने पांच पन्नों के संदर्भ पत्र में

14 सवाल रखे हैं, जिनका जवाब सुप्रीम कोर्ट से मांगा गया है। यह सवाल मुख्य रूप से अनुच्छेद 200 और 201 से जुड़े हैं, जिनमें राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों का जिक्र है।

राष्ट्रपति मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से पूछे ये 14 सवाल

राज्यपाल के समक्ष अगर कोई विधेयक पेश किया जाता है तो संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत उनके पास क्या विकल्प हैं?

क्या राज्यपाल इन विकल्पों पर विचार करते समय मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे हैं?

क्या अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल द्वारा लिए गए फैसले की न्यायिक समीक्षा हो सकती है?

क्या अनुच्छेद 361 राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 200 के तहत लिए गए फैसलों पर न्यायिक समीक्षा को पूरी तरह से रोक सकता है?

क्या अदालतें राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 200 के तहत लिए गए फैसलों की समयसीमा तय कर सकती हैं, जबकि संविधान में ऐसी कोई समयसीमा तय नहीं की गई है?

क्या अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा लिए गए फैसले की समीक्षा हो सकती है?

क्या अदालतें अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा फैसला लेने की समयसीमा तय कर सकती हैं?

अगर राज्यपाल ने विधेयक को फैसले के लिए सुरक्षित रख लिया है तो क्या अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की सलाह लेनी चाहिए?

क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति द्वारा क्रमशः अनुच्छेद 200 और 201 के तहत लिए गए फैसलों पर अदालतें लागू होने से पहले सुनवाई कर सकती हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 के द्वारा राष्ट्रपति और राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियों में बदलाव कर सकता है?

क्या अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की मंजूरी के बिना राय सरकार कानून लागू कर सकती है?

क्या सुप्रीम कोर्ट की कोई पीठ अनुच्छेद 145(3) के तहत संविधान की व्याख्या से जुड़े मामलों को सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच को भेजने पर फैसला कर सकती है? क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे निर्देश/आदेश दे सकता है जो संविधान या वर्तमान कानूनों मेल न खाता हो? क्या अनुच्छेद 131 के तहत संविधान इसको इजाजत देता है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुलझा सकता है?

तमिलनाडु केस और समय सीमा

8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु विधानसभा से पास हुए बिलों पर फैसला देते हुए पहली बार यह कहा था कि राष्ट्रपति को राज्यपाल की तरफ से भेजे गए किसी भी बिल पर तीन महीने के भीतर निर्णय लेना होगा। यह फैसला अपने आप में ऐतिहासिक माना गया क्योंकि इससे पहले ऐसी कोई समय सीमा तय नहीं थी।

पढ़े-लिखे आतंकवादी ज्यादा खतरनाक, दिल्ली दंगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बोली पुलिस

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में आज 2020 उत्तर-पूर्व दिल्ली दंगों को देश की आजादी पर हमला और सरकार बदलने की सोची-समझी साजिश करार दिया और उमर खालिद, शरजील इमाम समेत कई एक्टिविस्ट्स की जमानत याचिकाओं का गुरुवार को कड़ा विरोध किया। दिल्ली पुलिस ने लाल किले में हुए धमाके का हवाला देते हुए कहा कि जब पढ़े-लिखे बुद्धिजीवी आतंकवादी बन जाते है, तो वे जमीनी कार्यकर्ताओं से कहीं यादा खतरनाक हो जाते हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि अब डॉक्टरों और इंजीनियरों का देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होना एक ट्रेंड बन गया है। उन्होंने शरजील इमाम के कथित भड़काऊ भाषणों के वीडियो कोर्ट में दिखाया। वीडियो में इमाम को फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों से पहले 2019 और 2020 में चाखंड, जामिया, अलीगढ़ और आसनसोल में भाषण देते हुए

दिखाया गया था। वकील ने कहा कि आजकल एक ट्रेंड है कि डॉक्टर, इंजीनियर अपना प्रोफेशन नहीं कर रहे हैं बल्कि देश विरोधी कामों में लगे हुए हैं। जमानत के विरोध में दिल्ली पुलिस की ओर से ASG एस.वी. राजू ने कहा कि निचली अदालत को ट्रायल तेज करने का निर्देश दिया जा सकता है, लेकिन देरी जमानत का आधार नहीं। चाहे कोई 5.5 साल से जेल में हो, ये बेल देने का ग्राउंड नहीं होना चाहिए।

ट्रंप के दौरे के दौरान किया गया प्रोटेस्ट

स्त ने कहा कि सीएए प्रोटेस्ट को इंटरनेशनल मीडिया कवरेज पाने के लिए अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनल्ड ट्रंप के भारत दौरे के साथ टाइम किया गया था। राजू ने कहा कि इनका आखिरी इरादा सरकार बदलना है। सीएए के विरोध प्रदर्शन सिर्फ गुमराह करने वाले थे, असली मकसद सरकार बदलना, आर्थिक तंगी पैदा करना और पूरे देश में अफरा-तफरी फैलाना था। दंगे जानबूझकर US प्रेसिडेंट डोनल्ड ट्रंप के दौरे के साथ करवाए गए थे। ये तथाकथित बुद्धिजीवी जमीनी आतंकवादियों से यादा खतरनाक हैं।

एंटी-टेरर कानून के तहत मामला

खालिद, इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर और रहमान पर UAPA, जो सख्त एंटी-टेरर कानून है, और पहले के IPC के नियमों के तहत 2020 के दंगों के मास्टरमाइंड होने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था, जिसमें 53 लोग मारे गए थे और 700 से ज्यादा घायल हुए थे। यह हिंसा नागरिकता (संशोधन) एक्ट और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के दौरान भड़की थी। एक्टिविस्ट की जमानत याचिकाओं का कड़ा विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को तर्क दिया कि यह कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि देश की आजादी पर एक सोचा-समझा, पहले से प्लान किया हुआ और अच्छी तरह से डिजाइन किया गया हमला था।

कांग्रेस को असहज करने वाली तस्वीरः इंदिरा गांधी ट्रस्ट के कार्यक्रम में जगदीश टाइटलर, भाजपा का सीधा वार

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने गुरुवार को इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के एक कार्यक्रम में 1984 के सिख विरोधी दंगों के आरोपी जगदीश टाइटलर की कथित मौजूदगी को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि कांग्रेस ने चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में जगदीश टाइटलर को प्रमुख अतिथि के रूप में बिठाया। मालवीय ने कहा कि 1984 के सिख नरसंहार में टाइटलर की संलिप्तता पीड़ितों की गवाही, आयोगों और दशकों की खोजबीन के जरिए संदेह से परे साबित हो चुकी है। भाजपा नेता ने एक्स पर लिखा, गांधी परिवार द्वारा उन्हें संरक्षण देना और उन्हें वैध ठहराना सिख समुदाय के लिए एक भयावह संदेश है- कांग्रेस को 1984 के लिए न तो कोई पछतावा है और न ही कोई खेद। यह जानबूझकर किया गया कदम कोई संयोग नहीं है। यह इस बात की याद दिलाता है कि पार्टी भारत के सबसे काले और सबसे दर्दनाक अध्यायों में से एक को कितनी हल्के में लेती है। सिख समुदाय को इसे उसी रूप में देखना चाहिए जैसा यह है- यह एक राजनीतिक संकेत है कि कांग्रेस 1984 के नरसंहार में अपनी भूमिका को स्वीकार करने से इनकार करती है। इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता। स्मृतियों को दबाया नहीं जा सकता। और जवाबदेही को हमेशा के लिए नकारा नहीं जा सकता। पिछले साल, स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण समारोह के दौरान कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में टाइटलर की मौजूदगी ने विवाद खड़ा कर दिया था। मालवीय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा था- जगदीश टाइटलर, वह व्यक्ति जिसने राजीव गांधी के इशारे पर सिखों का नरसंहार किया था, एक बार फिर कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी के साथ देखा गया।

कुछ दाग मिटते नहीं, चाहे कितना भी समय बीत जाए। गांधी परिवार भी बेबाक है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए 1984 के सिख विरोधी दंगों में देश भर में 3,000 से ज्यादा सिख मारे गए थे। उस समय सबसे भीषण हिंसा दिल्ली में हुई थी।

दिल्ली ट्रेड फेयर का हुआ भव्य आगाज, तभी अचानक से पहुंच गए तालिबान के मंत्री

नई दिल्ली।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान (भारत मंडपम) में चल रहे 44वें इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में 19 नवंबरसे आमजन की एंट्री शुरू हो गई है। ऐसे में अब यहां रोजाना दर्शकों की अच्छी-खासी भीड़ देखने को मिल रही है। 27 नवंबर तक चलने वाले इस मेले में इस बार 12 देश और 30 राय एवं केंद्र शासित प्रदेश शिरकत कर रहे हैं। करीब एक दशक बाद रक्षा मंडप भी देखने को मिलेगा जहां आधुनिक हथियार ही नहीं, बल्कि प्रशिक्षित डाग स्कवायड के करतब भी देखे जा सकेंगे। तालिबान के वाणिय मंत्री नूरुद्दीन अजी का भारत दौरा खूब चर्चा में। वह पांच दिनों के लिए भारत आई और इस दौरान उनका मुख्य फोकस भारत अफगानिस्तान के व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करना है। अपने दौरे की शुरुआत में ही अजी सीधे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर पहुंचे। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में पहुंचकर उन्होंने कई स्टॉल्स भी देखे। उन्होंने वहां भारत में मौजूद अफगान कारोबारियों से बाजार की संभावनाओं पर बातचीत भी की। भारत के ट्रेड फेयर में किसी तालिबानी मंत्री का यह पहला दौरा है। क्योंकि 2021 के बाद से अफगानिस्तान से कोई बड़ा प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं हुआ था। बॉर्डर पर झड़प के बाद पाकिस्तान ने कई बार अपनी सीमाएं बंद कर दी जिससे अफगानिस्तान के फलों और अन्य निर्यात को भारी नुकसान हो रहा है और पाकिस्तान पर निर्भरता कम करने के लिए ही अफगानिस्तान अब भारत के साथ व्यापार बढ़ाने पर जोर दे रहा है और यही वजह है कि अजी का भारत आना और एक बड़े ट्रेड फेयर में शामिल होना पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका होगा। इससे साफ संकेत मिलता है कि अफगानिस्तान अब नए विकल्प खोज रहा है और भारत उसकी मदद के लिए आगे खड़ा है। अफगानिस्तान के मंत्रियों का भारत दौरा यह दिखाता है कि दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। भारत के ट्रेड फेयर में तालिबान के वाणिय मंत्री की मौजूदगी ना केवल दोनों देशों के बढ़ते आर्थिक रिश्तों का संकेत है बल्कि यह पाकिस्तान को यह संदेश भी देता है कि अफगानिस्तान अब व्यापार के लिए सिर्फ पाकिस्तान पर निर्भर नहीं है और अब वो उसकी निर्भरता से बाहर निकलकर वैकल्पिक साझेदारों की ओर बढ़ रहा है।

सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को मिली राहत, सेना टिप्पणी मामले में कोर्ट ने 4 दिसंबर तक टाली कार्यवाही

नई दिल्ली।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। यह राहत उन्हें भारतीय सेना पर कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़े एक मामले में दी गई है। अदालत ने राहत देते हुए उनके खिलाफ चल रही कार्यवाही पर लगी रोक को आगे बढ़ा दिया है।

कोर्ट इस पर अगली सुनवाई 4 दिसंबर को करेगा। एक मीडिया एजेंसी के अनुसार जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने मामले की सुनवाई को स्थगित करते हुए यह रोक आगे बढ़ाई। कोर्ट ने बताया कि स्थगन के लिए एक पत्र दिया गया था। राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें अधीनस्थ अदालत के समन आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को 29 मई को खारिज कर दिया गया था। यह मामला राहुल गांधी द्वारा दिसंबर 2022 में अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना पर की गई टिप्पणी से संबंधित है। राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया था कि चीनी सेना ने सीमा पर भारत का 2,000 वर्ग

किलोमीटर क्षेत्र कब्जा लिया है और अरुणाचल प्रदेश से भारतीय जवानों को खदेड़ दिया है। यह मामला लखनऊ की एक अदालत में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने चार अगस्त को इस मामले में आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। पिछले सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने राहुल गांधी के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश दिया था, लेकिन साथ ही उनकी टिप्पणी पर गहरी नाराजगी भी जताई थी।- आपको मीडिया या सोशल मीडिया पर ये सब कहने की क्या जरूरत थी? क्या आप वहां थे? आपको कैसे पता कि 2,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र कब्जा लिया गया है? क्या आपके पास कोई विश्वसनीय जानकारी है? बेंच ने स्पष्ट कहा था, बिना किसी सबूत के आप ये बयान क्यों दे रहे हैं? अगर आप सच्चे भारतीय हैं, तो आप ऐसी बात नहीं कहेंगे। राहुल गांधी के वकील सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत बोलने की आजादी के अधिकार की दलील दी थी, जिस पर कोर्ट ने असहमति जताई थी। कोर्ट ने कहा था कि उन्हें यह अधिकार है, लेकिन यह निरपेक्ष नहीं है।

नक्सलवाद पर बड़ा प्रहार एक नई सुबह की आहट

नक्सलवाद अपने अंतिम दौर में है और यह बड़ी उपलब्धि एवं परिवर्तन आकस्मिक नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की सुनियोजित, कठोर और व्यापक रणनीतियों का परिणाम है। वर्षों से जिस समस्या ने भारत के हृदयस्थल को रक्तरंजित किया था, जिस विचारधारा ने दशकों तक विकास, सुरक्षा और मानवीय संवेदनाओं को बंधक बनाए रखा था, वह अब लगभग समाप्ति की कगार पर पहुँच चुकी है। इसका सबसे बड़ा और हालिया प्रमाण है देश के सबसे खतरनाक, खूंखार और रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण माओवादी कमांडर माड़वी हिड़मा का खात्मा, एक ऐसा नाम जिसके आतंक ने न सिर्फ सुरक्षा बलों बल्कि पूरे तंत्र को लंबे समय तक चुनौती दी। सुकमा क्षेत्र में जन्मा हिड़मा, सीपीआई (माओवादी) की केंद्रीय समिति का सदस्य था और पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी की बटालियन-1 का प्रमुख। उसकी मौजूदगी मात्र से बड़े-बड़े हमले अंजाम दिए जाते थे। 2010 का दंतेवाड़ा हो या फिर 2013 का झीरम घाटी हमला, पिछले 20 बरसों में हुए लगभग सभी बड़े नक्सली हमलों के पीछे हिड़मा का हाथ माना जाता है। उसने लंबे अरसे तक दंडकारण्य में आतंक का राज कायम रखा। दरभा घाटी नरसंहार तक, सुरक्षा बलों के कई घातक ऑपरेशनों का गुनाहगार हिड़मा रहा। उसकी धमक इतनी थी कि उसके सिर पर 50 लाख से लेकर एक करोड़ रुपये तक का इनाम घोषित था। लेकिन 18 नवंबर 2025 को सुरक्षा बलों के एक अत्यंत सटीक और महत्वपूर्ण अभियान में हिड़मा और उसकी पत्नी राजे सहित छह माओवादी ढेर हुए। मौके से मिली एके-47, पिस्टल, राइफलें और अन्य हथियार यह प्रमाणित करते हैं कि यह ऑपरेशन नक्सलवाद की रीढ़ पर निर्णायक प्रहार है। हिड़मा का अंत प्रतीकात्मक ही नहीं, बल्कि रणनीतिक रूप से भी एक ऐसा क्षण है जिसने नक्सली नेटवर्क को हिला कर रख दिया है। लंबे समय से 'लाल गलियारा' कहे जाने वाले क्षेत्र की गतिविधियाँ जिस तेजी से सिकुड़ रही हैं, वह दर्शाता है कि केंद्र सरकार ने सुरक्षा और विकास दोनों मोर्चों पर जिस दोहरी रणनीति को अपनाया है, उसने वास्तविक जमीन पर असर दिखाया है। मार्च 2026 तक 'नक्सलमुक्त भारत' अभियान के अंतर्गत इस साल 300 नक्सली मारे गए, सैकड़ों गिरफ्तार हुए और आत्मसमर्पण किया-यह आँकड़े बताते हैं कि नक्सलवाद अब अपनी वैचारिक और संगठनात्मक शक्ति खो चुका है। हाल ही में छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में दो दिनों में सैकड़ों नक्सलियों का आत्मसमर्पण होना यह दर्शाता है कि नक्सल संगठन अब अपने आधार क्षेत्रों में भी समर्थन खो रहा है, और आदिवासी समाज धीरे-धीरे सरकारी विकास योजनाओं की ओर बढ़ रहा है। इसी परिवर्तन का सबसे बड़ा उदाहरण है हिड़मा का खात्मा, जिसने माओवादी कमान में एक ऐसा शून्य पैदा कर दिया है, जिसकी भरपाई उनके लिए आसान नहीं होगी। आतंकवाद की तरह ही नक्सलवाद भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक दीर्घकालिक, गहरी और जटिल चुनौती रहा है। जिस तरह सीमा पार से आने वाला आतंकवाद देश की शांति, विकास और सामाजिक सद्भाव के लिए खतरा बना हुआ था, उसी तरह भीतर से जन्मा नक्सलवाद राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया को बाधित करता रहा। दशकों तक यह समस्या न सिर्फ कुछ राज्यों के लिए, बल्कि पूरे भारत के लिए चिंता और असुरक्षा का कारण रही। लेकिन अब जिस निर्णायक मोड़ पर देश खड़ा है, वह यह संकेत देता है कि नक्सलवाद अपने अंतिम चरण में है। हाल के वर्षों में लगातार मिल रही सफलताएँ, शीर्ष नक्सली कमांडरों का सफाया, व्यापक आत्मसमर्पण, और प्रभावित क्षेत्रों में तेज विकास- ये सभी इस तथ्य को सिद्ध करते हैं कि देश एक नई सुबह की ओर बढ़ रहा है। यह वह सुबह है जो भारत को भय, हिंसा और पिछड़ेपन से मुक्त कर, स्थायी शांति और तेज विकास की ओर ले जाती है। नक्सलवाद की जड़ें स्वतंत्रता के बाद की सामाजिक-आर्थिक असमानताओं, भूमि अधिकारों और आदिवासी इलाकों की उपेक्षा में थीं। कई क्षेत्रों में विकास की रोशनी नहीं पहुँची थी, सरकारी योजनाएँ कागजों में रह जाती थीं, और स्थानीय समुदाय प्रशासन के प्रति अविश्वास से भरे हुए थे। इस वातावरण में नक्सली संगठनों को जमीन और जनसमर्थन मिला। उन्होंने वर्ग संघर्ष और हथियारबंद क्रांति के नाम पर हिंसा का मार्ग अपनाया, जंगलों को अपनी ढाल बनाया और आदिवासी युवाओं को अपने साथ जोड़ लिया। धीरे-धीरे यह आंदोलन एक साम्यवादी विचारधारा का रूप लेते हुए देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे खतरनाक चुनौती बन गया। लेकिन समय के साथ यह आंदोलन अपनी मूल विचारधारा से हटकर आतंक, वसूली, शोषण और खून-खराबे का अड्डा बन गया। सुरक्षा बलों पर हमले, विकास कार्यों को बाधित करना, पुलों और स्कूलों को उड़ाना, आदिवासियों को ढाल बनाना, और सत्ता हासिल करने की लालसा-यह सब नक्सलवाद की असलियत बन गया। इस मानसिकता ने न सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती दी, बल्कि हजारों परिवारों को तबाह किया और लाखों लोगों के जीवन को भय से भर दिया। लेकिन मोदी एवं शाह के प्रयासों से न केवल नक्सलवाद के खात्मे की सफल लड़ाई लड़ी गयी बल्कि नक्सल क्षेत्रों में विकास की योजनाओं को लागू किया गया। सड़क-बिजली-मोबाइल नेटवर्क जैसे क्षेत्रों में काफी काम हुआ है और इससे भी नक्सलियों की पकड़ कमजोर करने में मदद मिली है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2014 से अभी तक नक्सल प्रभावित इलाकों में 12 हजार किमी से ज्यादा सड़कें बनी है, बैंकों की हजार से ज्यादा शाखाएं खोली गई है और स्किल डिवेलपमेंट पर काम किया जा रहा है। इन समन्वित प्रयासों से ही नक्सली जड़ से उखड़ेंगे। माड़वी हिड़मा जैसे अत्यंत खूंखार और रणनीतिक दिमाग वाले नेता का मारा जाना, नक्सलवाद की रीढ़ तोड़ने जैसा है। हिड़मा न सिर्फ नक्सलियों की सैन्य रणनीतियों का प्रमुख दिमाग था, बल्कि उसकी छवि ने वर्षों तक सुरक्षा बलों में चुनौती की भावना जगाई रखी।

नक्सलवाद के कमजोर होने में केवल सुरक्षा अभियानों की भूमिका नहीं है, बल्कि राजनीतिक इच्छाशक्ति सबसे महत्वपूर्ण रही है। जब सरकार ने स्पष्ट किया कि देश को -नक्सलवाद मुक्त भारत- बनाना है, तो उसके लिए बहु-स्तरीय रणनीति अपनाई गई। एक ओर सुरक्षा बलों को आधुनिक तकनीक, बेहतर प्रशिक्षण और सटीक इंटेलिजेंस से मजबूत किया गया, वहीं दूसरी ओर सड़कें, स्कूल, अस्पताल, दूरसंचार और आजीविका कार्यक्रमों द्वारा विकास को तेज किया गया। विकास और सुरक्षा का यह संयुक्त प्रभाव नक्सलवाद की जड़ों को खोखला करने में निर्णायक सिद्ध हुआ है। देश के सामने जो नई सुबह उभर रही है, उसका अर्थ सिर्फ यह नहीं कि बंदूकें शांत हो जाएँगी। इसका अर्थ यह भी है कि वे क्षेत्र, जो दशकों से पिछड़े थे, अब देश की मुख्यधारा से जुड़ेंगे। वहाँ निवेश होगा, शिक्षा और स्वास्थ्य का ढाँचा मजबूत होगा, पर्यटन और स्थानीय उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, और लोग भय-मुक्त होकर जीवन जी पाएँगे। नक्सलवाद के पतन का संदेश यह भी है कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी हिंसक विचारधारा से अधिक शक्तिशाली है। हथियार, भय और आतंक से सत्ता पाने का कोई भी प्रयास अंततः असफल होता है। जनता की आकांक्षाएँ सदैव विकास, सुरक्षा और शांति में होती हैं। नक्सली आंदोलन की जैसी समाप्ति दिख रही है, वह इस सत्य को और अधिक स्पष्ट करती है।

नक्सलवाद की पूर्ण समाप्ति केवल बंदूक से नहीं होगी। इसके लिए आवश्यक है कि सरकार विकास योजनाओं की निरंतरता बनाए रखे, आदिवासी समुदायों को सशक्त करे, स्थानीय संस्कृति और संभावनाओं का सम्मान करे, और यह सुनिश्चित करे कि प्रशासनिक व्यवस्था पारदर्शी और संवेदनशील बने। यदि यह निरंतरता जारी रहती है, तो नक्सलवाद का पुनरुत्थान असंभव हो जाएगा। नक्सलवाद का लगभग खत्म होना भारत के लिए सिर्फ एक सुरक्षा उपलब्धि नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक मोड़ है।

सम्पादकीय...

विकास के मंत्र

भाजपा ने क्या किया जो राहुल, तेजस्वी और प्रशांत नहीं कर पाए! बिहार के चुनाव परिणाम ने देश में एक नई बहस भी छेड़ दी है, लोगों के बीच अब इस मुद्दे पर बहस हो रही है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के सामने किसी का भी चुनाव जीतना अब नामुमकिन है? ज्यादातर लोगों की राय यह बन रही है कि बीजेपी और पीएम मोदी को हराना नामुमकिन नहीं भी है तो यह मुश्किल जरूर है। फिर इसके अलग-अलग कारणों के विश्लेषण भी किए जाते हैं। इसमें अधिकतर लोगों का मानना है कि बीजेपी अब एक चुनावी मशीन बन गई है जो पूरे समय काम करती रहती है। बीजेपी में नेताओं की भूमिका पहले तय हो जाती है और नेतृत्व के बनाए कार्यक्रम के अनुसार काम होता है। इसका उदाहरण है, बिहार के चुनाव में प्रमुख नेताओं की समय से पहले तैनाती। जब नीतीश कुमार 2022 में बीजेपी को छोड़ कर एक बार फिर आरजेडी के साथ चले गए थे तभी राष्ट्रीय महासचिव तावड़े को बिहार जा कर चुनाव की तैयारी में अभी से जुट जाने का निर्देश दे दिया था। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी तब सक्रिय होते है, जब चुनाव सिर पर होता है, धरातल पर ना तो उनकी टीम नजर आती है और ना सक्रिय कार्यकर्ता। भाजपा के लिए चुनाव तैयारी कोई पार्ट टाइम गेम नहीं है, बल्कि यह जनता से जुड़े रहने और मुद्दों के आसपास पार्टी को तैयार रखने का सतत् अभियान है। भाजपा की जिस चुनावी रणनीति का लोग आज लोहा मान रहे हैं उसे विकसित करने और उसकी धार बनाए रखने की जिम्मेदारी स्वयं गृह मंत्री अमित शाह निभाते है। अमित शाह ने ही गुजरात में अपने कार्यकाल के दौरान चुनाव तंत्र को विकसित किया था और 2014 के बाद से इसे लगातार देशव्यापी अभियान का इसे हिस्सा बना रहे हैं। बीजेपी नेतृत्व को बिहार की नब्ज का अंदाज था। खास कर अमित शाह ने अपनी तीन महीने के धुआंधार दौरे से यह अंदाज लगा लिया था कि जनता क्या चाहती है और उसी के अनुसार जब केंद्र और राज्य सरकार ने बिहार की जनता की अपेक्षाओं को पूर्ण करने का काम पूरा किया तो जनता गद्‌गद् हो उठी। फिर जनता ने यह अनुमान भी लगा लिया कि केंद्र में मोदी की डबल इंजन सरकार के साथ बिहार तेज रफ्तार से प्रगति करेगा। वोट चोरी, ईवीएम सेटिंग आदि सब बचकाना बातें हैं। अमित शाह पहले नेता थे जिन्होंने एक चुनावी रैली में ही यह ऐलान कर दिया था कि इस बार एनडीए 160 से ज्यादा सीटें जीतेगा और बिहार में सरकार बनाएगा। फिर अंतिम चरण के मतदान से कुछ ही दिन पहले एक रैली में शाह ने फिर घोषणा की कि 14 नवंबर राजद और कांग्रेस परिवारों के राजनीतिक सफाए का दिन होगा। यदि अमित शाह ने चुनावी सफलता का कोई रिकार्ड बनाया है तो इसके पीछे उनका अनथक परिश्रम है। पार्टी में रणनीति और उस पर क्रियान्वयन के लिए पूरी तरह से समर्पित कार्यकर्ताओं के निर्माण की एक बड़ी प्रक्रिया है। कांग्रेस का संगठन बिहार में भी गायब है और केवल गाली-गलौच की सुर्खियों तक ही सीमित है। इस बार बिहार में अमित शाह ने पार्टी को एकजुट और अनुशासित रखने में भी अपना भरपूर योगदान किया। चुनाव नजदीक आते-आते बागियों की संख्या नाम मात्र की रह गई। महादलित-पासी-पासवान मतदाताओं को लोजपा और मजबूत स्थानीय उम्मीदवारों के माध्यम से एकजुट करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी लेकिन आरजेडी अंत तक एमवाई समीकरण के भरोसे रह गए। कांग्रेस के पास उनको जोड़ने का ना कोई नारा था और न कोई नेता। इस मामले में राहुल गांधी केवल तेजस्वी पर निर्भर थे। नीतीश कुमार अभी भी कोइरी-कुर्मी मतदाताओं के बीच अपना दबदबा सबसे ज्यादा रखते है, उसे कम करने का प्रयास भी आरजेडी ने नहीं किया। जदयू और भाजपा के नेतृत्व ने संयुक्त प्रचार अभियानों ने एनडीए के आधार को इन वर्गों में और मजबूत किया। अमित शाह ने उच्च-जाति समूहों में भी लगातार बैठकें की। आरजेडी ने दूरी बनाए रखी। बीजेपी ने अपना पहला फोकस महिलाओं पर रखा, क्योंकि उनको मालूम था कि परिवार की धुरी महिला चुनाव परिणाम में एक बड़ी भूमिका निभा सकती है। बीजेपी ने हर कार्यकर्ता को महिलाओं से जुड़ी एनडीए सरकार की योजनाओं को उन तक पहुंचाने का निर्देश दिया। बिहार में सीता मैया का भव्य मंदिर बने और उसका सीधा जुड़ाव अयोध्या के मंदिर से हो, यह बात बताना अमित शाह किसी भी रैली में नहीं भूले। राहुल और तेजस्वी इस तरह के मुद्दे को इस डर से नहीं उठाते कि मुसलमान नाराज हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जोरदार तरीके से विकास का एजेंडा लोगों के सामने रखा और बिहार को एकीकृत विकास पैकेज देने का भी वायदा किया। पीएम मोदी द्वारा जंगलराज और वंशवाद की राजनीति पर भी तीखा प्रहार किया गया, जिस पर राहुल और तेजस्वी का जवाब लोगों के समक्ष में नहीं आया। आरजेडी और कांग्रेस दोनों नीतीश सरकार के 20 साल के शासन के खिलाफ जनता में आक्रोश की उम्मीद करते रह गए और एनडीए उसी को अपने लिए विश्वास के प्लेटफॉर्म के रूप में बखूबी इस्तेमाल कर लिया। यहां कोई अलाउद्दीन का चिराग नहीं था, बल्कि नीतीश का काम था जो बोल रहा था। उनकी जबान नहीं काम शोर करता है।

'मुस्लिम-लीग माओवादी कांग्रेस' का मतलब क्या?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कांग्रेस को 'मुस्लिम-लीग माओवादी कांग्रेस' कहने और उसे 'देश के लिए खतरा' बताने का निहितार्थ क्या है? इस विचार को प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार नहीं बल्कि 3 अवसरों पर व्यक्त किया है। पहले 14 नवम्बर को बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा नीत राजग गठबंधन द्वारा दर्ज प्रचंड जीत पर दिल्ली में भाजपा समर्थकों को संबोधित करते हुए। फिर 15 नवम्बर को गुजरात स्थित सूरत के एक कार्यक्रम में और इसके बाद 17 नवम्बर को दिल्ली में आयोजित रामनाथ गोयनका के व्याख्यान में। प्रधानमंत्री के मुताबिक, ''10-15 साल पहले कांग्रेस में जो अर्बन-नक्सली माओवादी पैर जमा चुके थे, अब वो कांग्रेस को 'मुस्लिम-लीग माओवादी कांग्रेस' (एम.सी.सी.) बना चुके है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि मुस्लिम-लीग माओवादी कांग्रेस अपने स्वार्थ में देश के लिए खतरा बनती जा रही है।'' कांग्रेस की यह छवि एकाएक नहीं बनी है और न ही यह मात्र कोई चुनावी या राजनीतिक जुमलेबाजी है। कांग्रेस का संकट बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे पर उसके आधिकारिक वक्तव्य से स्पष्ट है, जिसमें पार्टी नेतृत्व मतदाता द्वारा नकारे जाने को फर्जी 'वोट चोरी' का परिणाम बता रही है। दरअसल, वर्तमान कांग्रेस के शीर्ष नेता और लोकसभा में नेता-विपक्ष राहुल गांधी जिस विभाजनकारी मार्ग पर चल रहे है,उसकी प्रेरणा उन्हें अपने परिवार ही से मिली है। वर्ष 1950 से राहुल के परनाना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस विकृत सैकुलरवाद को अपनाया, उसने देश में इस्लामी कट्टरता और हिंदू-विरोधी शक्तियों को नया जीवनदान दिया। पहले उन्होंने जम्मू-कश्मीर के इस्लामी स्वरूप को बरकरार रखने हेतु अनुच्छेद 370-35ए को संविधान में बिना चर्चा के 'चोर दरवाजे' से शामिल करवाया तो बहुसंख्यकों के लिए 'हिंदू कोड बिल' लागू करके मजहबी स्वतंत्रता के नाम पर मुस्लिम समाज को हलाला और तीन तलाक जैसी कुरीतियों के साथ छोड़ दिया। पं. नेहरू के लिए हिंदू मंदिर 'दमनकारी' तो केवल हिंदू ही 'सांप्रदायिक' थे। कालांतर में उनके द्वारा अपनाई समाजवाद प्रेरित नीतियों ने भारतीय आर्थिकी को ध्वस्त कर दिया, जिसकी चर्चा पिछले कुछ लेखों में की जा चुकी है। यह विकृति राहुल की दादी इंदिरा गांधी के शासन में और बढ़ गई। उन्होंने 1969 में कांग्रेस टूटने के बाद अपने धड़े की वैचारिक संगोष्ठी उन वामपंथियों के हाथों में सौंप दी जो अधिनायकवाद को बढ़ावा देने के साथ न तो तब स्वयं को भारत की बहुलतावादी सनातन संस्कृति से जोड़ पाए थे न ही अब जोड़ पाते हैं। इसके परिणामस्वरूप, अदालत द्वारा अपनी 'वोट चोरी' पकड़े जाने पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश पर आपातकाल (1975-77) थोप दिया। इसी दौरान अयोध्या में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की श्रीरामजन्मभूमि मंदिर के प्रमाण संबंधित उत्खनन रिपोर्ट को भी दबा दिया गया। कालांतर में पंजाब में अपने विरोधी अकाली दल को हाशिए पर पहुंचाने हेतु उन्होंने मृत 'खालिस्तान' विचार को अपने क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ और सत्ता हथियाने की लालसा में पुनर्जीवित कर दिया। इसका उल्लेख गैर-राजनीतिक, पूर्व आई.पी.एस. अधिकारी और भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग' (रॉ) में वर्षों जुड़े रहने के बाद सेवानिवृत्त हुए गुरबख्श सिंह सिद्धू ने अपनी पुस्तक 'द खालिस्तान कांस्पिरेसी' में किया है। जैसे 1980 के दशक में भिंडरांवाले को आगे रखकर इंदिरा गांधी ने हिंदू-सिख संबंधों को लेकर आत्मघाती राजनीति की, ठीक उसी तरह राहुल के पिता राजीव गांधी ने वर्ष 1986 के शाहबानो मामले से 'मुस्लिम वोटबैंक' का बिगुल फूंक दिया। तब मुस्लिम कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेकते हुए तत्कालीन राजीव सरकार ने संसद में प्रचंड बहुमत के बल पर मुस्लिम महिला उत्थान की दिशा में आए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को पलट दिया था। कालांतर में मुस्लिम-विरोध के कारण ही सलमान रशीद की 'सैटनिक वर्सेज'(1988)और तस्लीमा नसरीन की 'लज्जा' (1993) पुस्तकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। भले ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता (दिवंगत) डा.मनमोहन सिंह 2004-2014 के बीच देश के प्रधानमंत्री रहे परंतु उन्हें दिशा-निर्देश असंवैधानिक 'राष्ट्रीय सलाहकार परिषद' (एन.ए.सी.) से मिलते थे, जिसका नेतृत्व तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्षा और राहुल की माता जी सोनिया गांधी कर रही थी। एन.ए.सी.में ऐसे लोग शामिल थे,जिनका राष्ट्रहित की बजाय वैचारिक एजेंडे (वामपंथ सहित) से अधिक सरोकार था। इसी कालखंड में 2002 के उस नृशंस गोधरा कांड, जिसमें जिहादियों ने भजन-कीर्तन कर रहे 59 हिंदुओं को ट्रेन में जिंदा जला दिया था, उसे 'हादसा' बताकर रफा-दफा करने का असफल प्रयास किया गया। घुमा-फिराकर 'देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का' बता दिया। हलफनामा देकर सर्वोच्च न्यायालय में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम को काल्पनिक कह दिया।

शाह का प्रण पूरा होगा?

अमित शाह स्वतन्त्र भारत के ऐसे पहले गृहमन्त्री हैं जिन्होंने देश से नक्सलवाद और माओवादी हिंसा को समाप्त करने का लक्ष्य रखा और उसे समय से पूरा करने की रणनीति तैयार की। उन्होंने नक्सलवादियों से बातचीत का रास्ता नहीं चुना बल्कि उनके द्वारा आत्मसमर्पण करने को अपना अभीष्ट बनाया। श्री शाह बहुत सख्त गृहमन्त्री माने जाते हैं क्योंकि हिंसा के मामले में उनका दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से नक्सलियों द्वारा आत्मसमर्पण का है। श्री शाह ने देशवासियों को आश्वासन दिया है अगले वर्ष अप्रैल महीने तक नक्सलवाद जड़ से समाप्त हो जायेगा। अपने इसी प्रण को पूरा करने की दिशा में उन्होंने नक्सलवादियों को चुनौती दी कि उनके किसी भी बड़े से बड़े सरगना को छोड़ा नहीं जायेगा। इस सिलसिले में कल ही सुरक्षा बलों ने आन्ध्र प्रदेश के जंगलों में एक करोड़ के इनामी दुर्दान्त माओवादी कमांडर माड्वी हिड़मा को मार गिराया और उसके साथ अन्य पांच नक्सलियों को भी मौत के घाट उतार दिया। हिड़मा को छत्तीसगढ़ का आतंक भी कहा जाता था। उसे मार गिरा कर सुरक्षा बलों ने अपने नक्सली हिंसा को समाप्त करने के अभियान को निर्णायक सफलता की ओर बढ़ा दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि श्री शाह के दृढ़ रुख को देखते हुए देशभर से नक्सलियों व माओवादियों का सफाया निश्चित प्रायः है। श्री शाह को जहां एक तरफ भाजपा का चाणक्य कहा जाता है वहीं दूसरी ओर उन्हें अपना वचन हर कीमत पर रखने वाले नेता के रूप में भी देखा जाता है। श्री शाह ने बहुत पहले ही यह घोषणा कर दी थी कि आगामी वर्ष के अप्रैल महीने तक नक्सली आतंकवाद को जड़ से समाप्त कर दिया जायेगा। इसी क्रम में श्री शाह ने सुरक्षा बलों को लक्ष्य दिया था कि वे 30 नवम्बर तक दुर्दान्त माओवादी माड्वी हिड़मा को जिन्दा या मुर्दा पकड़ें। सुरक्षा बलों ने 18 नवम्बर को ही हिड़मा का खात्मा करके साफ कर दिया है कि आगामी 30 नवम्बर तक वे अन्य नक्सलियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हिड़मा इतना खूंखार था कि वह नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों पर किये गये 26 हमलों में शामिल था। उसकी पत्नी राजे भी उसके कारनामों में शामिल रहती थी। मगर पुलिस व अन्य केन्द्रीय सुरक्षा बलों ने जो माओवादियों व नक्सलियों को समाप्त करने का अभियान छेड़ रखा है उसे देखते हुए कहा जा सकता है श्री शाह का देशवासियों को दिया गया आश्वासन पक्के तौर पर पूरा होगा। हिड़मा के मारे जाने से छत्तीसगढ़ के जंगल ज्यादा सुरक्षित हो सकेंगे। दरअसल नक्सलवाद भारत के भीतर ऐसी समस्या है जिसका निदान केवल हिंसा के रास्ते को छोड़ देना ही है। दरअसल नक्सलवाद एक ऐसी मानसिकता है जो भारतीय संविधान को नहीं मानती और अपना ही शासन चलाये रखने की बात करती है और बखान करती है कि सत्ता बन्दूक की नली से पैदा होती है न कि चुनावों से। पिछली मनमोहन सरकार के दौर में यह समस्या अपने उग्र रूप में थी। छत्तीसगढ़ में नक्सली सबसे ज्यादा प्रभावी थे। अतः इस राज्य के बस्तर व सुकमा जिले घोषित रूप से नक्सली हिंसा के शिकार थे। नक्सलवाद पर संसद में भी गंभीर चर्चा कई बार हुई है।

पराजय के दुष्चक्र में फंसे राहुल गांधी

कांग्रेस ने 61 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसे मात्र छह सीटें मिलीं। यह पराजय नहीं, पतन है और इसके केंद्र में हमेशा की तरह राहुल गांधी हैं। लगभग दो दशक से राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय राहुल बीच-बीच में अपने शब्दाडंबरों और सोशल मीडिया घोषणाओं के साथ दिखते हैं, फिर उसी तेजी से गायब हो जाते हैं। कभी वह सक्रिय कार्यकर्ता की भूमिका निभाते हैं, पर नेपथ्य में चले जाते हैं। इसका कांग्रेस पर भीषण असर पड़ा है। इसने न सिर्फ अपनी मास अपील खो दी है, बल्कि पराजय के एक ऐसे चक्र में फंस गयी है जिससे बाहर निकलने की क्षमता उसमें नहीं दिखती। राहुल गांधी 2004 में राजनीति में आये। वर्ष 2009 से वह पार्टी के फैसलों को प्रभावित करने लगे थे। तब से देशभर में हुए 83 विधानसभा चुनावों में से 71 में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 44 सीटों पर सिमट गयी थी। उसके इस बदतर प्रदर्शन पर उसके आलोचक भी स्तब्ध थे। फिर 99 सीटों तक पहुंचने में पार्टी को एक दशक लग गया। राज्यों में उसकी शक्ति का क्षय तो और भी चौंकाने वाला है। वर्ष 2014 में देश के 11 राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थीं।

शुरूआत फुसफुसाहट से नहीं, गंगा के मैदान के आर-पार राजनीतिक विस्फोट से हुई। पिछले सप्ताह बिहार ने जो जनादेश दिया वह कांग्रेस के लिए इतना अपमानजनक था कि उसके घनघोर समर्थकों के लिए भी उसे हजम करना मुश्किल है। कांग्रेस ने 61 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसे मात्र छह सीटें मिलीं। यह पराजय नहीं, पतन है और इसके केंद्र में हमेशा की तरह राहुल गांधी हैं। लगभग दो दशक से राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय राहुल बीच-बीच में अपने शब्दाडंबरों और सोशल मीडिया घोषणाओं के साथ दिखते हैं, फिर उसी तेजी से गायब हो जाते हैं। कभी वह सक्रिय कार्यकर्ता की भूमिका निभाते हैं, पर नेपथ्य में चले जाते हैं। इसका कांग्रेस पर भीषण असर पड़ा है। इसने न सिर्फ अपनी मास अपील खो दी है, बल्कि पराजय के एक ऐसे चक्र में फंस गयी है जिससे बाहर निकलने की क्षमता उसमें नहीं दिखती। राहुल गांधी 2004 में राजनीति में आये। वर्ष 2009 से वह पार्टी के फैसलों को प्रभावित करने लगे थे। तब से देशभर में हुए 83 विधानसभा चुनावों में से 71 में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 44 सीटों पर सिमट गयी थी। उसके इस बदतर प्रदर्शन पर उसके आलोचक भी स्तब्ध थे। फिर 99 सीटों तक पहुंचने में पार्टी को एक दशक लग गया। राज्यों में उसकी शक्ति का क्षय तो और भी चौंकाने वाला है। वर्ष 2014 में देश के 11 राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थीं। आज केवल तीन राज्यों-कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में इसकी सरकारें हैं। कभी पूरे नक्शे पर फैली हुई राष्ट्रीय पार्टी आज कुछ टुकड़ों में सिमट गयी है। इसकी विधानमंडलीय शक्ति भी इसके पतन के बारे में बताती है। देशभर में कांग्रेस विधायकों की संख्या एक दशक में आधी रह गयी है। अब जो बचा है, वह एक थकी हुई पार्टी के चुके हुए नेतागण, जर्जर ढांचा और ध्वस्त बुनियाद है। किसी भी संदर्भ में यह त्रासद है। पर नेहरू-गांधी परिवार के लिए तो यह बेहद चौंकाने वाला है। अपने समकालीनों की तुलना में तो राहुल संघर्ष कर ही रहे हैं, अपने परिवार के नेताओं की तुलना में भी वह कमतर साबित हुए हैं।

उनके परनाना जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता थे और उन्होंने लगातार तीन लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को भारी मतों से जीत दिलायी थी। नये गणतंत्र की वैचारिक और प्रशासनिक बुनियाद गढ़ने वाली नेहरू की कांग्रेस की तीन-चौथाई से भी अधिक राज्यों में सरकारें थीं। इंदिरा गांधी की राजनीतिक समझ बहुत तेज और चुनावी वर्चस्व बेजोड़ था। उन्होंने भी तीन लोकसभा चुनाव जीते, जिनमें से दो में उन्हें भारी बहुमत मिला था। उनके नेतृत्व में फिर से देश के दो-तिहाई से अधिक राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनीं। राहुल की मां सोनिया गांधी ने भी वह हासिल किया जो असंभव लग रहा था। उन्होंने 2004 में केंद्र की सत्ता में कांग्रेस की वापसी का पथ प्रशस्त किया। हालांकि वह वंशवादी रास्ते से नहीं, बल्कि कुशल राजनीतिक रणनीति के जरिये था। उन्होंने गठबंधन बनाये, विपरीत वैचारिकता वाली पार्टियों को साथ लिया और मनमोहन सिंह को गठबंधन सरकार का प्रधानमंत्री बनाया। वर्ष 2009 में उनके दिशा-निर्देश में कांग्रेस ने दूसरा लोकसभा चुनाव जीता। राहुल गांधी इससे एकदम विपरीत हैं और नेहरू-गांधी खानदान के सबसे विफल राजनीतिक वारिस हैं। उनके पूर्वजों ने कांग्रेस का विस्तार किया, जबकि उनके दिशा-निर्देश में पार्टी सिकुड़ रही है। उनके पूर्वजों ने जहां सरकारें चलायीं, वहीं उनके समय में कांग्रेस सांस लेने के लिए संघर्ष कर रही है। यह स्थिति आयी है तो इसके कारण न तो छिपे हुए हैं, न ही रहस्यपूर्ण है। राहुल ने वैकल्पिक सरकार का कोई नक्शा तैयार नहीं किया है। घनघोर वैचारिक संघर्षों और सुस्पष्ट प्रशासनिक वादों के बीच उनके संदेश बिखरे हुए, अनियमित और अस्पष्ट हैं। उन्होंने एकजुटता का कोई विमर्श तैयार नहीं किया, न कोई यादगार नारा गढ़ा, न ही सामाजिक, आर्थिक या संस्थानिक तौर पर पार्टी को लोगों से जोड़ने का कोई काम किया, जिसकी आज कांग्रेस को सबसे ज्यादा जरूरत है।

भारतीय लोकतंत्र एक कमजोर विपक्ष के सहारे नहीं चल सकता। विपक्ष कमजोर है तो इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस की है। इसके बावजूद यह पार्टी आज सुस्पष्ट वैचारिकता के बजाय उसी परिवार द्वारा चालित है, जिसके प्रति कभी जातियों, क्षेत्रों और वर्गों की असंदिग्ध निष्ठा थी। आज यह पार्टी तो अपने काडर तक को प्रेरित नहीं कर पा रही है।

कांग्रेस के अंदर बहुतेरे लोग कहते हैं कि गांधी ब्रांड चुनाव जीतने की क्षमता खो चुका है। यह ब्रांड पार्टी को विखंडन से भले बचा ले लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी को खड़ा नहीं कर सकता। राहुल के दिशा-निर्देश में कांग्रेस का संगठन बिखर चुका है। करिश्माई और प्रतिस्पर्धी राज्य स्तरीय नेताओं का न होना पार्टी के लिए घातक है। दक्षिण में फिर भी कांग्रेस के कुछ शक्तिशाली गढ़ हैं। पर राजनीतिक रूप से निर्णायक हिंदी पट्टी यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और पंजाब जैसे राज्यों में भाजपा के स्थानीय नेतृत्व को चुनौती देने लायक नेताओं को तराशने में राहुल विफल हुए हैं। यह सिर्फ रणनीतिक विफलता नहीं, पार्टी के लिए आत्मघाती भी है। यहां तक कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी गठबंधन बनाने के मामले में राहुल की निष्क्रियता भी चौंकाने वाली है। देश के दूसरे सबसे बड़े राजनीतिक दल के नेता के तौर पर भाजपा के खिलाफ मोर्चेबंदी में उन्हें प्रमुख रणनीतिकार होना चाहिए था लेकिन उनकी आधी-अधूरी प्रतिबद्धता के कारण इंडिया गठबंधन बिखरने के कगार पर है। कांग्रेस अगर अब भी भारत के लोकतांत्रिक भविष्य में अपनी भूमिका देखती है तो उसे तत्काल अपनी श्रेष्ठता ग्रंथि से बाहर निकलना होगा। उसे एक ऐसा नेता ढूंढना होगा जो सत्ता का भूखा हो लेकिन जल्दबाज नहीं, जो कभी-कभी नजर आने के बजाय हमेशा दिखता हो और प्रभाव पैदा करने के बजाय जो स्पष्ट विचारधारा का हो। कांग्रेस को एक ऐसा नेता चाहिए जो भ्रमण पर निकलने के बजाय रोज राजनीतिक युद्ध छेड़ने की मानसिकता रखता हो। या तो कांग्रेस खुद को नये सिरे से खड़ा करने का उद्यम ले, या जब भारतीय राजनीति का केंद्र स्थायी रूप से शिफ्ट हो रहा है तब राजनीति के फुटनोट में अपनी मौजूदगी दर्ज करना जारी रखे।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने कन्हा ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, सराय पीपलथला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2019/[illegible])

पड़ोसियों के साथ रखें अच्छा व्यवहार: मौलाना फलाही

पड़ोसियों के अधिकारों पर जमात-ए-इस्लामी हिन्द ने दस दिवसीय देशव्यापी अभियान का किया शुभारंभ

मुरादाबाद।

जमात-ए-इस्लामी हिन्द, उत्तर प्रदेश पश्चिम के अमीर-ए-हल्का मौलाना ज़मीर हसन खां फ़लाही ने (पड़ोसी अधिकार) विषय पर आधारित दस दिवसीय विशेष अभियान के शुभारंभ की घोषणा की है। यह अभियान ÷मिसाली पड़ोस ङ्क मिसाली समाज÷ के नारे के साथ 21 नवंबर से 30 नवंबर तक पूरे हल्के में संचालित किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य पड़ोसियों के साथ सौहार्द, भलाई, सहयोगपूर्ण संबंधों तथा सामाजिक रिश्तों को मजबूत करने की भावना को पुनर्जीवित करना है। मीडिया के लिए जारी बयान में मौलाना ज़मीर हसन खां फ़लाही ने कहा कि इस्लाम पड़ोसियों के अधिकारों को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान देता है और इसे शांतिपूर्ण एवं सामंजस्यपूर्ण समाज की नींव मानता है। उन्होंने कहा कि कुरआन ने स्पष्ट रूप से यह निर्देश दिया है कि मुसलमान न केवल अपने करीबी पड़ोसियों, बल्कि सहकर्मियों, सहयात्रियों और राहगीरों तक के साथ भी उत्तम व्यवहार करें। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य इन शिक्षाओं की याद दिलाना तथा मुसलमानों को एक आदर्श पड़ोसी बनने की प्रेरणा देना है, ताकि व्यापक समाज के सामने इस्लाम का वास्तविक और सुंदर चरित्र प्रस्तुत किया जा सके। मौलाना ज़मीर हसन खां फ़लाही ने कहा कि अच्छा पड़ोस किसी भी आदर्श समाज की बुनियाद है। जब लोग अपने पड़ोसियों के साथ नर्मी, सहनशीलता और न्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं तो इससे पूरे समाज में सकारात्मक परिवर्तन उत्पन्न होता है। उन्हें उम्मीद है कि यह अभियान न केवल आपसी विवादों को कम करने में मददगार साबित होगा बल्कि इस्लामी मूल्यों, सामाजिक ज़िम्मेदारी और हृदय की संवेदनशीलता का महत्वपूर्ण संदेश भी देगा। अभियान के पश्चिमी उत्तर प्रदेश कन्वीनर मौलाना अतीक अहमद इस्लाही ने बताया कि शहरी जीवन में बढ़ती दूरी, अकेलेपन और पड़ोसी संबंधों की कमजोरी को देखते हुए अभियान की रूपरेखा तैयार की गई है।

उन्होंने कहा कि इस अभियान के प्रमुख उद्देश्यों में आपसी हृदयता, सहयोग, स्वच्छता और यातायात अनुशासन जैसी जिम्मेदारियों को इस्लामी सामाजिक कर्तव्य के रूप में प्रोत्साहित करना शामिल है। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान अनेक गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी, जिनमें विभिन्न धर्मों के पड़ोसियों से मुलाक़ात, चाय परिचर्चाएँ, महिलाओं और युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम, सफाई अभियान, ट्रैफिक जागरूकता रैलियाँ और सांस्कृतिक प्रतियोगिताएँ शामिल हैं। अभियान के अंतर्गत गैर-मुस्लिम भाइयों एवं बहनों से संबंधों को प्रगाढ़ बनाने, अंतरधार्मिक सौहार्द को बढ़ावा देने और इस्लाम के प्रति व्याप्त भ्रांतियों को दूर करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही ÷अपने पड़ोसी को जानिए÷ जैसे कार्यक्रम, मोहल्लों में सांस्कृतिक सभाएँ तथा फॉलो-अप के लिए स्थानीय समितियों का गठन भी किया जाएगा, ताकि यह संबंध अभियान के बाद भी कायम रह सकें।

एसआईआर व पुनरीक्षण में शिथिलता पाये जाने पर दण्डित होंगे अधिकारी : डीएम

बहराइच।

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचक नामावली के वृहद् पुनरीक्षण, 2025 में संभावित डुप्लीकेट वोटरों के सत्यापन व विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण एस.आई.आर. अन्तर्गत संचालित गतिविधियों की समीक्षा के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिया कि निर्वाचन जैसे अतिमहत्वपूर्ण कार्य को भारत निर्वाचन आयोग व राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए समयबद्धता के साथ पूर्ण किया जाय। डीएम ने जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सचेत किया कि किसी प्रकार की शिथिलता पाये जाने पर आयोग के संज्ञान में लाते हुए सम्बन्धित के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी।

विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण एस.आई.आर. की समीक्षा करते हुए समस्त ईआरओ/उप जिलाधिकारी तथा एईआरओ/बीडीओ, बीईओ व चकबन्दी अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर 50 प्रतिशत डिजीटाइज़ेशन का कार्य पूर्ण कर लिया जाय। डीएम श्री त्रिपाठी ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश दिया कि सीडीपीओ के अधीन कार्यरत सभी अधिकारी व कर्मचारी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचक नामावली के वृहद् पुनरीक्षण एवं एसआईआर के कार्य में सहयोग प्रदान करें। विधानसभावार समीक्षा के दौरान पयागपुर व बलहा को प्रगति में अपेक्षित सुधार लाने के निर्देश दिये गये। सभी ईआरओ को यह भी निर्देश दिया गया कि अपरिहार्य व विषम परिस्थितियों में ही बूथ लेबिल अधिकारियों को बदला जाये। पंचायत निर्वाचक नामावली में प्रदर्शित हो रहे। सम्भावित डुप्लीकेट मतदाताओं के सत्यापन के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी/ सहा. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पं.), तहसीलदार/ अति. सहा. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पं.), बीडीओ व बीईओ को निर्देश दिया गया कि एक सप्ताह में शेष सम्भावित डुप्लीकेट मतदाताओं पर अन्तिम रूप से निर्णय लेकर ऑनलाइन फीडिंग करा दिया जाए। सहयोग के लिए रोजगार सेवक, शिक्षामित्र, अध्यापकों, सहायिकाओं का विशेष सहयोग लिया जाय। डीएम ने यह भी निर्देश दिया कि 30 नवम्बर 2025 तक क्वांटम पूरा कर लिया जाय। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी अमित कुमार, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार तथा सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी व खण्ड शिक्षा अधिकारी मौजूद रहे।

श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वीं शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में विशेष ट्रेनों का संचालन

गोरखपुर ।

भारतीय रेल श्री गुरु तेग बहादुर जी–सिखों के नौवें गुरु, तथा हिंद दी चादर–की पावन शहादत को नमन करते हुए विशेष ट्रेनों की एक श्रृंखला चलाने जा रही है।

यह सूचना देते हुए रेल एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी की सर्वोच्च शहादत सत्य, न्याय और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा का अमर संदेश है। भारतीय रेल इस पावन अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं की यात्रा को सहज, सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए कृतसंकल्पित है। श्री रवनीत सिंह ने बताया कि भारतीय रेल श्री आनन्दपुर साहिब और दिल्ली की ओर जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दो विशेष ट्रेन सेवाओं का संचालन करेगी। ये ट्रेनें बड़े पैमाने पर यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए अधिकतम सुविधा और सहजता सुनिश्चित करेंगी।

1. पटना साहिब विशेष ट्रेन (सभी श्रेणी)

*22 कोच वाली यह विशेष ट्रेन 23 नवंबर को सुबह 6:40 बजे पटना से प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 4:15 बजे आनन्दपुर साहिब पहुँचेगी।

*वापसी यात्रा 25 नवंबर को रात 9:00 बजे आनन्दपुर साहिब से शुरू होगी और उसी दिन रात 11:30 बजे पुरानी दिल्ली पहुँचेगी।

*मार्ग में लखनऊ, मुरादाबाद और अम्बाला स्टेशनों पर ठहराव होगा।

2. पुरानी दिल्ली विशेष ट्रेन (सभी एसी)

*यह 17 कोचों वाली विशेष सेवा 22, 23, 24 और 25 नवंबर को प्रतिदिन सुबह 7:00 बजे पुरानी दिल्ली से चलेगी और दोपहर 1:45 बजे आनन्दपुर साहिब पहुँचेगी।

*वापसी यात्रा प्रतिदिन रात 8:30 बजे आनन्दपुर साहिब से प्रारंभ होकर सुबह 3:15 बजे दिल्ली पहुँचेगी।

*दोनों दिशाओं में ट्रेन सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, सरहिंद और न्यू मोरिंडा स्टेशनों पर रुकेगी।

श्री रवनीत सिंह ने कहा कि ये विशेष ट्रेनें श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित, आरामदायक और सुलभ बनाने के भारतीय रेल के दृढ़ संकल्प का प्रतीक हैं। भारतीय रेल गुरु तेग बहादुर जी की अमर विरासत को नमन करते हुए सभी श्रद्धालुओं के लिए सेवा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

छात्रवृति के लिए समय सारणी में बदलाव

मुरादाबाद। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी तुलिका शर्मा ने बताया कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति (कक्षा 11-12 को छोड़कर) योजना के अन्तर्गत वंचित समस्त वर्गों के छात्र/छात्राओं के लिए संशोधित समय सारणी जारी की गयी है। उन्होंने बताया कि शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा लॉक करने की तिथि 20 नवम्बर से 26 नवम्बर 2025 तक है, विश्वविद्यालय/एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा फीस आदि के सत्यापन की तिथि 01 दिसम्बर 2025 है, जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा फीस आदि के सत्यापन की तिथि 04 दिसम्बर 2025 है, छात्रों द्वारा रजिस्ट्रेशन/ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 20 नवम्बर से 26 नवम्बर 2025 तक है, शिक्षण संस्थाओं द्वारा आवेदन पत्र को ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित किये जाने की तिथि 03 दिसम्बर 2025 है, विश्वविद्यालय/एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लॉक करने की तिथि 04 दिसम्बर से 09 दिसम्बर 2025 तक है, जनपदीय समिति द्वारा डाटा लॉक करने की तिथि 16 दिसम्बर 2025 से 05 जनवरी 2026 तक है एवं धनराशि के अन्तरण की तिथि 12 जनवरी 2026 निर्धारित है।

बाढ़ एवं अतिवृष्टि से प्रभावित 5421 किसानों के खाते में भेजे गए 2.49 करोड़ रुपए

मुरादाबाद। वर्ष 2025 में आई बाढ़/अतिवृष्टि के कारण जनपद के प्रभावित 5910 कृषकों के सापेक्ष 5421 कृषकों के खाते में करीब 2.49 करोड़ रूपए भेजे जा चुके हैं। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ममता मालवीय ने बताया कि अवशेष 489 कृषकों के बैंक खाते अपडेट न होने के कारण भुगतान नहीं हो पाया है। संबंधित तहसीलदार द्वारा इन सभी कृषकों से पुनः सही बैंक खाता प्राप्त कर भुगतान की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि लाभार्थियों में तहसील मुरादाबाद के 3459, तहसील कांठ के 1148, तहसील ठाकुरद्वारा के 783 और तहसील बिलारी के 31 कृषक शामिल हैं।

कुंदरकी में विधायक की अगुवाई में निकला यूनिटी मार्च

मुरादाबाद।

भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर कुंदरकी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह के नेतृत्व में एक विशाल यूनिटी मार्च एकता पदयात्रा निकाली गई। इस अवसर पर विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने उपस्थित नागरिकों और विद्यार्थियों को देश की एकता-अखंडता बनाए रखने तथा नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। यह एकता पदयात्रा कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र के चारों मंडलो से होती हुई शिव मंदिर गोविंदपुर कलां चौराहा पर एकत्र होकर प्रारम्भ हुई और कल्याण सिंह पब्लिक स्कूल सैफपुर पल्ला में संपन्न हुई, जहाँ समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कल्याण सिंह पब्लिक स्कूल सैफपुर पल्ला में समापन कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता और सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्रों पर माल्यार्पण के साथ हुआ। समापन कार्यक्रम पर आयोजित सभा में पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष सूर्य प्रकाश पाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए, उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आजादी के बाद सरदार वल्लभभाई पटेल ने अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए 500 से अधिक रियासतों का आजाद भारत में विलय कराया। उन्होंने देश की एकता और अखंडता को मजबूत किया। सूर्य प्रकाश पाल ने आगे कहा कि जब भारत एक हो गया और उसकी एकता-अखंडता मजबूत हो गई, तब इसकी सुरक्षा पर विचार-विमर्श शुरू हुआ। कुंदरकी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने बताया कि सरदार पटेल के एक भारत-श्रेष्ठ भारत के सपने को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं। गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है, जो देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है। उन्होंने आगे कहा कि पूरे देश में ऐसी एकता यात्राएं निकाली जा रही हैं, जो एकता और अखंडता का संदेश देती हैं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय गौरव जगाना, एकता की भावना को मजबूत करना और सरदार पटेल के एक भारत, अखंड भारत के अटूट विश्वास को आगे बढ़ाना है। कार्यक्रम में एमएलसी जयपाल सिंह व्यस्त, जिला अध्यक्ष आकाश पाल, जिला महामंत्री कमल कुमार प्रजापति, ब्लॉक प्रमुख डॉ नवदीप यादव , मंडल अध्यक्ष महेंद्र सैनी, नीरज चंद्रा, संजय कश्यप , बबलू जाटव , जिला पंचायत सदस्य जेपी सैनी, रोहित सिंह, सोनू रस्तौगी, रविंद्र सिंह, नसीम खान, संजय दिवाकर, अरविन्द ठाकुर सहित बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं, भाजपा पदाधिकारी एवं स्थानीय नागरिक उत्साहपूर्वक शामिल हुए।

एमसीडी उपचुनाव : कांग्रेस ने तैयार की रणनीति, हर बूथ पर बीजेपी-आप की कमजोरियां उजागर करने की तैयारी

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बूथ स्तर तक अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने चुनावी तैयारी को नए सिरे से व्यवस्थित किया है और पार्टी कार्यकर्ताओं को ऐसे उपकरण सौंपे हैं, जिससे न सिर्फ चुनाव प्रबंधन आसान होगा बल्कि विपक्षी दलों की नाकामियों को भी सीधे मतदाताओं तक पहुंचाया जा सकेगा। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने सभी 12 वार्डों के बूथ स्तर पर तैनात कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एक विशेष किट सौंपी है। मजबूत दिल्ली कांग्रेस लेबल वाले इस बैग में वोटर लिस्ट, पम्पलेट, स्टीकर, कांग्रेस बिल्ला और बीजेपी-आप सरकारों की नाकामियों पर आधारित एक विस्तृत दस्तावेज शामिल है। इस मौके पर एआईसीसी के दिल्ली प्रभारी काजी निजामुद्दीन, चुनाव कमेटी चेयरमैन राजेश गर्ग, जिला अध्यक्ष राज कुमार जैन, मोहम्मद उस्मान, जगजीवन शर्मा और अशोक जैन भी मौजूद रहे।

मतदाताओं तक पहुंचने और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की रणनीति

देवेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस के बूथ कार्यकर्ता हर मतदाता तक पहुंचकर कांग्रेस की विचारधारा और पूर्व कांग्रेस सरकारों के विकास कार्यों को समझाएंगे। साथ ही, वे बीजेपी और आप सरकार की कमियों को भी लोगों के सामने रखेंगे। उन्होंने बताया कि पार्टी ने सभी वार्डों में बूथ कमेटियां गठित कर दी है और हर कार्यकर्ता को ड्यूटी स्पष्ट कर दी गई है। इससे चुनाव प्रचार को एक मजबूत दिशा मिलेगी। यादव ने कहा कि बूथ प्रबंधन कमेटियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है ताकि वे अपने बूथ पर अधिकतम सतर्कता बनाए रखें। उनका कहना था कि बीजेपी की वोट चोरी जैसी हेराफेरी से मतदाताओं को जागरूक करना भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का लक्ष्य रहेगा। उन्होंने बताया कि चुनाव के दिन हर बूथ पर कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे, मतदान प्रक्रिया पर नजर रखेंगे और बोगस वोटिंग रोकने के लिए पूरी सजगता से जिम्मेदारी निभाएंगे। चुनाव आयोग के कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर रखते हुए निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने का प्रयास भी उनके एजेंडे में है। बता दें कि दिल्ली नगर निगम की 12 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के नोटिफिकेशन के मुताबिक 30 नवंबर को सभी 12 सीटों पर मतदान होगा जिसके नतीजे 3 दिसम्बर को जारी किए जाएंगे। उपचुनाव मुंडका, शालीमार बाग-बी, अशोक विहार, चांदनी चौक, चांदनी महल, द्वारका-बी, दिचाऊं कलां, नारायणा, संगम विहार-ए, दक्षिण पुरी, ग्रेटर कैलाश और विनोद नगर में होंगे। दिल्ली की विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा जीत दर्ज करने के बाद एमसीडी में 12 सीट खाली हो गए, इनमें शालीमार बाग-बी वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाली रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गयी हैं, जबकि द्वारका-बी वार्ड से बीजेपी की महिला नेता कमलजीत सहरावत पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद के रूप में चुनी गई। वहीं, बाकी वार्ड बीजेपी और आप के मौजूदा पार्षदों द्वारा फरवरी में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने से खाली हुए थे।

नीतीश 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री

26 मंत्रियों ने भी शपथ ली; इनमें भाजपा के 14, जदयू के 8, चिराग के 2 मंत्री; एक मुस्लिम चेहरा

-: नई कैबिनेट के मंत्रियों की लिस्ट :-

सम्राट चौधरी	सुनील कुमार
विजय कुमार सिन्हा	मोहम्मद जमा खान
विजय कुमार चौधरी	संजय सिंह टाइगर
बिजेंद्र प्रसाद यादव	अरुण शंकर प्रसाद
श्रवण कुमार	सुरेंद्र मेहता
मंगल पांडेय	नारायण प्रसाद
दिलीप जायसवाल	रमा निषाद
अशोक चौधरी	लखेंद्र कुमार रौशन
लेशी सिंह	श्रेयसी सिंह
मदन सहनी	डॉ. प्रमोद कुमार
नितिन नबीन	संजय कुमार
राम कृपाल यादव	संजय कुमार सिंह
संतोष कुमार सुमन	दीपक प्रकाश

पटना।

आज बिहार में नई सरकार का गठन हो गया है। जदयू प्रमुख नीतीश कुमार ने गुरुवार को रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। उनके साथ सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा सहित 26 मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सभी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा और एनडीए के कई अन्य शीर्ष नेता शामिल हुए। जेडीयू के विजय कुमार चौधरी, बिजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार और अशोक चौधरी ने गुरुवार को बिहार के मंत्री पद की शपथ ली। वहीं बीजेपी के दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे, संजय सिंह टाइगर, रमा निषाद, अरुण शंकर प्रसाद, राम कृपाल यादव और नितिन नबीन और सुरेंद्र प्रसाद मेहता ने भी मंत्री पद की शपथ ली। बता दें कि जनता दल यूनाइटेड सुप्रीमो नीतीश कुमार ने नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के 202 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करने के बाद बिहार में सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उन्होंने कल बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की और मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया। एनडीए ने 2025 के बिहार असेंबली चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जिसमें 243 में से 202 सीटें जीतीं। सत्ताधारी गठबंधन ने 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा में तीन-चौथाई बहुमत हासिल किया, यह दूसरी बार है जब एनडीए ने राज्य चुनावों में 200 सीटों का आंकड़ा पार किया। 2010 में, इसने 206 सीटें जीती थीं।

दिल्ली धमाका मामला: चार और आरोपी गिरफ्तार, एनआईए टीम ने जम्मू-कश्मीर से हिरासत में लिया

नई दिल्ली।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के बाहर हुए विस्फोट में शामिल चार और मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके बाद इस मामले में गिरफ्तारियों की कुल संख्या छह हो गई है। पटियाला हाउस कोर्ट के जिला सत्र न्यायाधीश के पेशी आदेश पर एनआईए ने चारों आरोपियों को जम्मू और कश्मीर से हिरासत में लिया है।

सभी ने हमले में निभाई अहम भूमिका

एनआईए ने आरोपियों की पहचान पुलवामा (जम्मू-कश्मीर) निवासी डॉ. मुजम्मिल शकील गनई, अनंतनाग (जम्मू-कश्मीर) निवासी डॉ. अदील अहमद राथर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) निवासी डॉ. शाहीन सईद और शोपियां (जम्मू-कश्मीर) निवासी मुफ्ती इरफान अहमद वागे के रूप में की है। एनआईए की जांच के अनुसार, इन सभी ने इस आतंकवादी हमले में अहम भूमिका निभाई थी, जिसमें कई

निर्दोष लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हुए थे।

पहले हो चुकी इनकी गिरफ्तारी

मामले की जांच में तेजी लाते हुए, एनआईए ने पहले ही दो अन्य आरोपियों आमिर राशिद अली, जिसके नाम पर विस्फोट में इस्तेमाल की गई कार पंजीकृत थी और जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश, जिसने इस घातक हमले में शामिल आतंकवादी को तकनीकी सहायता प्रदान की थी, को गिरफ्तार कर लिया था। आर सी-21/2025 /एनआईए/डीएलआई मामले में पूरी आतंकी साजिश का पर्दाफाश करने के एनआईए के प्रयासों के तहत उनसे पूछताछ जारी है।

धमाके में अब तक हुई 15 लोगों की मौत

गौरतलब है कि 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए धमाके में 15 निर्दोष लोगों की मौत हुई थी और कई घायल हुए थे। एनआईए ने कहा है कि जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और आने वाले दिनों में और भी खुलासे हो सकते हैं। एजेंसी ने इस मॉड्यूल के अन्य सदस्यों और इसके सपोर्ट नेटवर्क की पहचान के लिए तलाशी अभियान और पूछताछ की प्रक्रिया भी तेज कर दी है।

जम्मू में कश्मीर टाइम्स के ऑफिस में एनआईए की छापामारी, एके-47 के कारतूस बरामद

जम्मू। जम्मू-कश्मीर पुलिस की स्टेट इंवेस्टिगेशन एजेंसी ने गुरुवार को जम्मू स्थित कश्मीर टाइम्स के कार्यालय पर छापामारी की। एजेंसी ने यह कार्रवाई उन आरोपों के आधार पर की है, जिनमें अखबार पर राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल होने और देश के खिलाफ असंतोष फैलाने का आरोप लगाया गया है। छापे में एके-47 राइफल के कारतूस, पिस्टल के कुछ राउंड और हैंड ग्रेनेड पिन समेत दूसरी चीजें जब्त कीं।

आईएएफ का इजरायली ड्रोन जैसलमेर के पास क्रैश, जांच के आदेश जारी

नई दिल्ली।

जैसलमेर के रामगढ़ बॉर्डर इलाके में एक खेत में इंडियन एयर फोर्स का एक टूटा हुआ अनमैन्ड एरियल व्हीकल मिला है। पुलिस ने ये जानकारी दी। रामगढ़ पुलिस स्टेशन के असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर प्रेम शंकर ने बताया कि यूएवी को भारत-पाकिस्तान बॉर्डर के पास मोहनगढ़ नंबर 3, सत्तार मढ़नर के एक खेत से बरामद किया गया। उन्होंने आगे बताया कि रामगढ़ पुलिस स्टेशन की एक टीम सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। बाद में, आईएएफ के अधिकारी मौके पर पहुंचे और यूएवी को अपने कब्जे में ले लिया।

बिना प्लान के ही नहीं, ये खतरनाक भी है, एसआईआर पर ममता बनर्जी की ईसी को चिट्ठी

बंगाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को राज्य में मतदाता सूचियों के संरचनात्मक रूप से अस्वस्थ विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभ्यास पर अपनी चिंता व्यक्त की। 20 नवंबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लिखे एक पत्र में मुख्यमंत्री बनर्जी ने दावा किया कि प्रशिक्षण में गंभीर कमियाँ, अनिवार्य दस्तावेजीकरण पर स्पष्टता का अभाव और अपनी आजीविका के व्यस्त कार्यक्रमों के बीच मतदाताओं से मिलना लगभग असंभव होने के कारण यह अभ्यास संरचनात्मक रूप से अस्वस्थ हो गया है। मुख्यमंत्री ने चल रहे एसआईआर के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की, जिसमें अपर्याप्त योजना, प्रशिक्षण की कमी और अवास्तविक समयसीमा का हवाला दिया गया, जो प्रक्रिया की विश्वसनीयता से समझौता कर रहे हैं। पत्र में लिखा है कि मैंने बार-बार चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और जिस तरह से इसे लोगों पर थोपा जा रहा है, उसके संबंध में अपनी गंभीर चिंताओं को उठाया है।

अब, मैं आपको यह लिखने के लिए बाध्य हूं क्योंकि चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़ी स्थिति बेहद चिंताजनक स्तर पर पहुँच गई है। जिस तरह से यह प्रक्रिया अधिकारियों और नागरिकों पर थोपी जा रही है, वह न केवल अनियोजित और अव्यवस्थित है, बल्कि खतरनाक भी है। बुनियादी तैयारी, पर्याप्त योजना या स्पष्ट संचार के अभाव ने पहले दिन से ही इस प्रक्रिया को पंगु बना दिया है। मुख्यमंत्री बनर्जी ने बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) पर अत्यधिक कार्यभार और दबाव को उजागर किया, जो ऑनलाइन डेटा प्रविष्टि, सर्वर समस्याओं और अपर्याप्त प्रशिक्षण से जूझ रहे हैं, जिससे गलत मतदाता डेटा का खतरा है। पत्र में कहा गया मैं इन अत्यंत विकट परिस्थितियों और भारी कार्यभार के बीच बीएलओ द्वारा किए गए अथक प्रयासों की तहे दिल से सराहना करती हूं।

हालांकि, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बीएलओ को इस तरह के विशाल कार्य के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण, सहायता और समय नहीं दिया गया है। अवास्तविक कार्यभार, असंभव समय-सीमा और ऑनलाइन डेटा प्रविष्टि के लिए अपर्याप्त सहायता ने सामूहिक रूप से पूरी प्रक्रिया और उसकी विश्वसनीयता को गंभीर खतरे में डाल दिया है। यह हमारे चुनावी लोकतंत्र की नींव पर प्रहार है। उन्होंने आगे दावा किया कि बीएलओ अब मानवीय सीमाओं से कहीं आगे जाकर काम कर रहे हैं। उनसे अपने मुख्य कर्तव्यों (जिनमें से कई शिक्षक और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता हैं) को संभालने की उम्मीद की जाती है, साथ ही साथ घर-घर जाकर सर्वेक्षण और जटिल ई-प्रस्तुतियों को भी संभालना होता है। अधिकांश बीएलओ प्रशिक्षण की कमी, सर्वर की विफलता और बार-बार डेटा बेमेल होने के कारण ऑनलाइन फॉर्म भरने में संघर्ष कर रहे हैं।

चुनाव आयोग पर बरसीं ममता, एसआईआर अभ्यास में गंभीर खामियां

आदिवासी समुदायों का विकास प्राथमिकता, उग्रवाद पर लगाम: राष्ट्रपति मुर्मू का छत्तीसगढ़ में बड़ा ऐलान

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुवार को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अंबिकापुर में बिरसा मुंडा सहित आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को सम्मानित करने के लिए आयोजित जनजातीय गौरव दिवस में शामिल हुईं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि आदिवासी समुदायों का योगदान भारत के इतिहास में एक गौरवशाली अध्याय है। आदिवासियों का विकास भारत सरकार की प्राथमिकता है। आदिवासी समुदायों के कल्याण के लिए विभिन्न राष्ट्रीय स्तर की योजनाएँ विकसित और कार्यान्वित की गई हैं। राष्ट्रपति ने राज्य की प्रगति के लिए लोगों को बधाई दी। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि मैं छत्तीसगढ़ के लोगों को उनकी प्रगति के लिए बधाई देती हूं। उन्होंने अभी-अभी राज्य गठन की रजत जयंती मनाई है।

मुझे भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली (झारखंड में) जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भारतीय इतिहास में आदिवासी समुदायों का योगदान अतुलनीय रहा है। छत्तीसगढ़ आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। झारखंड और ओडिशा छत्तीसगढ़ से ज्यादा दूर नहीं हैं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे राज्य ने अपनी संस्कृति को संरक्षित रखा है, जो सार्वजनिक स्थानों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। मुर्मू ने कहा कि जब मैं हेलीपैड से यहाँ आ रही थी, तो रास्ते में छत्तीसगढ़ की संस्कृति साफ दिखाई दे रही थी। राज्य ने अपनी संस्कृति को संरक्षित रखा है जो बहुत प्रभावशाली और मनभावन है... मुझे आदिवासी होने पर बहुत गर्व है। आदिवासी कला और संस्कृति को देश के साथ-साथ विदेशों में भी और अधिक बढ़ावा देने की आवश्यकता है। उन्होंने वामपंथी उग्रवाद का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होने के लिए लोगों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ सहित देश भर के लोग वामपंथी उग्रवाद का रास्ता छोड़कर विकास की मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के सुविचारित और सुव्यवस्थित प्रयासों से निकट भविष्य में वामपंथी उग्रवाद का उन्मूलन संभव हो जाएगा। इससे पहले, राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सरगुजा जिले के अंबिकापुर पहुँचने पर राष्ट्रपति मुर्मू का स्वागत किया। इससे पहले, केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगामी छत्तीसगढ़ दौरे का स्वागत करते हुए कहा कि यह राज्य के लिए गर्व की बात है।

नीतीश कुमार के सीएम पद पर वापसी पर अखिलेश यादव की बधाई, समाजवादी मूल्यों वाले शासन की जताई उम्मीद

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गुरुवार को जनता दल (यूनाइटेड) के नेता नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी और पूरे पाँच साल के कार्यकाल के लिए शुभकामनाएँ दीं। अपने संदेश में, अखिलेश यादव ने कहा कि नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री पद पर लौटना बिहार के राजनीतिक परिदृश्य के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अपने लंबे सार्वजनिक जीवन और प्रशासनिक अनुभव के लिए जाने जाने वाले नीतीश कुमार विकास और सामाजिक न्याय पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करते हुए राज्य का नेतृत्व करेंगे। अखिलेश यादव ने इस बात पर प्रकाश डाला कि नीतीश कुमार ने समाजवादी मूल्यों पर आधारित शासन की लगातार वकालत की है और आशा व्यक्त की कि उनका नया कार्यकाल समावेशिता, कल्याणकारी नीतियों और जनहितैषी निर्णय लेने के सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करेगा। उन्होंने कहा कि मैं श्री नीतीश कुमार जी को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर हार्दिक बधाई देता हूं। मैं उनकी मूल समाजवादी विचारधारा पर आधारित एक स्वतंत्र शासन मॉडल को अगले पाँच वर्षों तक सफलतापूर्वक चलाने और लोगों के लिए सकारात्मक और कल्याणकारी पहल सुनिश्चित करने की भी कामना करता हूं। समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश गहरे सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक संबंध साझा करते हैं और आशा व्यक्त की कि दोनों पड़ोसी राज्य क्षेत्रीय विकास के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। नीतीश कुमार ने आज दिन में अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ शपथ ली। अखिलेश यादव का संदेश देश भर के नेताओं की बधाई प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला में जुड़ गया है, जिससे बिहार में एक नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत हुई है।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज सहित 175 हस्तियों का पत्र- विपक्ष से कहा- बिहार का जनादेश अस्वीकार करें

हैदराबाद। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी. सुदर्शन रेड्डी सहित 175 प्रमुख हस्तियों ने बिहार चुनाव, चुनाव आयोग और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर खुला पत्र लिखा है। इन दिग्गज हस्तियों ने बिहार चुनाव परिणाम को धोखाधड़ी माना है और विपक्षी से आग्रह किया है कि वह इन नतीजों को स्वीकार न करे। खुले पत्र में कहा गया, हम देश के नागरिक पूरी तरह पारदर्शी, जवाबदेह, मुक्त और निष्पक्ष चुनावों की मांग करते हैं। हम बिहार चुनाव परिणाम को धोखाधड़ी मानते हैं और विपक्ष से भी यही मांग करते हैं कि वह इन परिणामों को स्वीकार न करे। इन हस्तियों ने आगे कहा कि एसआईआर की मौजूद प्रणाली एक ऐसी सरकार की इच्छा पूरी करती है, जो किसी भी तरह सत्ता बनाए रखना चाहती है। बदलाव के नाम पर मनमानी चुनाव प्रक्रिया होती है। हमने दर्शक, विश्लेषक और टिप्पणीकार के रूप में यह सब देखा है कि यह बदली हुई व्यवस्था कैसे लोकतंत्र पर असर डालती है और पारदर्शी, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांतों को नजरअंदाज करती है। उन्होंने आगे कहा, यह हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान की रक्षा की लड़ाई का एक नया अध्याय है। अब धोखाधड़ी का खेल खुले तौर पर सामने आ गया है। मतदाताओं को जानबूझकर हटाया जा रहा है और उतनी ही सावधानी से नए मतदाता जोड़े जा रहे हैं, ताकि एक खास ताकत के उम्मीदवार जीत सकें। हम बिहार की जनता के साथ खड़े हैं और इन चुनाव परिणामों को

■ **नामचीन हस्तियों का खुला पत्र– जनादेश में गड़बड़, विपक्ष नतीजे ठुकराए**

अस्वीकार करते हैं। पत्र में आगे कहा गया, चुनाव आयोग के अनुसार एसआईआर प्रक्रिया 2003 की प्रक्रिया पर आधारित है, लेकिन वास्तव में उससे कोई मेल नहीं खाती। इसमें चालाकी से हर मतदाता के लिए एक नया फॉर्म जोड़ दिया गया है, जिससे उन्हें दोबारा मतदाता सूची में नाम लिखवाना पड़ता है। नाम हटाने की प्रक्रिया और अंतिम सूची किसी तरह की पारदर्शिता नहीं दिखाती और कोई जवाबदेही नहीं लेती। यह बदली हुई प्रक्रिया एक भेदभावपूर्ण सूची देती है, जिसमें बिहार में लाखों लोग मताधिकार से वंचित हो गए। इन प्रमुख हस्तियों ने आगे कहा, हम भारत के मतदाताओं के रूप में एकजुट होकर खड़े हैं। हम मानते हैं कि कोई भी योग्य मतदाता नहीं छूटना चाहिए। हमें राजनीतिक विपक्ष से निराशा है, क्योंकि उन्होंने इस बदली हुई चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लिया। लोगों के बीच मतदाता अधिकार यात्रा को समर्थन मिलने के बावजूद चुनाव में शामिल होना धोखाधड़ी से बनी इस सरकार को वैधता देता है। इसके अलावा, विपक्ष ने देश के जमीनी नागरिक संगठनों के साथ रणनीतिक रूप से काम करने की भी कम क्षमता दिखाई है। नागरिक समाज ने इस चुनावी संकट के दौर में कई प्रभावी कदम उठाए हैं। हम विपक्षी दलों से अपील करते हैं कि वे बिहार चुनावों से सीख लें और मिलकर ऐसा माहौल बनाएं जिससे लोकतंत्र मजबूत हो सके। उन्हें जनता के साथ मिलकर लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा, जैसे-जैसे आगे 12 और राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया लागू होने वाली है, हम चुप नहीं बैठेंगे। चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल दिख रहा है और लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहा है। चुनाव आयोग ने उन मूल्यों को ठेस पहुंचाई है, जिन पर उसका निर्माण हुआ था। इन प्रमुख हस्तियों ने आरोप लगाया कि मौजूदा नेतृत्व में चुनाव आयोग एक रक्षक की जगह भक्षक का काम कर रहा है। हम भारत के चुनाव आयोग को उसकी मौजूदा स्थिति में वैध नहीं मानते। हम एक बार फिर एक निष्पक्ष, गैर-राजनीतिक और संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप चुनाव आयोग के लिए संघर्ष करेंगे। खुले पत्र में हस्ताक्षर करने वाली हस्तियों में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के पूर्व अधिकारी देवसयाम एमजी, राजनीतिक अर्थशास्त्री और लेखक परकला प्रभाकर, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज शंकर केजी, फिल्म अभिनेता प्रकाश राज, तकनीकी और सुरक्षा सलाहकार माधव देशपांडे, जनतंत्र समाज (बिहार) के राम शरण, बिहार के सामाजिक कार्यकर्ता राशिद हुसैन जैसे नाम शामिल हैं।

नीतीश के रिकॉर्ड पर तेजस्वी की बधाई, नई सरकार से बताई ये बड़ी उम्मीद

पटना। नीतीश कुमार के लगातार पांचवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन को बधाई देते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि नई सरकार लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरेगी। बिहार के मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद तेजस्वी ने ट्वीट किया कि नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर हार्दिक बधाई। राजद नेता ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि नई सरकार जिम्मेदार नागरिकों की आकांक्षाओं और उम्मीदों पर खरी उतरेगी, अपने वादों और घोषणाओं को पूरा करेगी और बिहार के लोगों के जीवन में सकारात्मक और गुणात्मक बदलाव लाएगी।

5 साल तक सीएम रहेंगे- सिद्धारमैया ने नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को किया खारिज

नई दिल्ली। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार को नवंबर क्रांति की खबरों को खारिज करते हुए इसे मीडिया की उपज बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनका रुख शुरू से ही मजबूत रहा है और आगे भी रहेगा। यह पूछे जाने पर कि क्या वह 5 साल तक सीएम बने रहेंगे, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि यह एक अनावश्यक बहस है। यह कहा गया था कि ढाई साल बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल

किया जा सकता है, उसके बाद ही मुख्यमंत्री बदलने का मुद्दा सामने आया है। पार्टी नेताओं को कैबिनेट फेरबदल पर फैसला लेने की जरूरत है। कुल 34 मंत्री पद हैं, जिनमें से दो पद खाली हैं। कैबिनेट फेरबदल के दौरान इन खाली मंत्री पदों को भरा जाएगा। उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के सीएम बनने के बयान पर एक सवाल के जवाब में सिद्धारमैया ने कहा कि मैं ऐसे किसी बयान का जवाब नहीं दूंगा। कांग्रेस पार्टी राज्य में पांच साल से सत्ता में है और उसके पास जनादेश है। हमारे घोषणापत्र में किए गए वादे को पूरा करने के लिए ईमानदार प्रयास किया जा रहा है। मीडिया ने नवंबर क्रांति का मुद्दा बनाया। जनता की इच्छा के अनुसार, पांच साल के शासन के बाद कांग्रेस पार्टी फिर से चुनी जाएगी। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि जनता ने कांग्रेस को पांच साल के लिए सत्ता सौंपी है। उन्होंने सत्ता-बंटवारे पर चर्चा पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि जनता ने हमें पांच साल शासन करने का जनादेश दिया है।